खाद्यान्नों मदों में नाशी जीव

319. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "भोजन में कीशनाशकों की बढ़ती मात्रा अब लोगों के लिए भी जानलेवा" शीर्षक से 15-1-99 को दैनिक जागरण में छपी खबर के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई छानबीन की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल) : (क) से (ग) यह समाचार दिल्ली और राजस्थान की सात भैसों और मथुरा के एक सूअर के शवों की टांगों की मांसपेशियों का विज्ञान तथा पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली (एक गैर सरकारी संगठन) द्वारा आई टी कानपुर में कराए गए विश्लेषण से संबंधित है। विश्लेषण के परिणामों में डी डी टी और बी एच सी विद्यमान पाए गए हैं।

सरकार को मानव को कीटनाशक अवशिष्टों से होने वाले जोखिम की जानकारी है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (स्वस्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू) के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में अवशिष्टों के पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती हैं। उल्लिखित समाचार में ऐसा कोई मामला नहीं हैं। तथापि, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) जन सेवा कार्यक्रम के लिए सीमित उपयोग के अलावा कृषि में डी डी टी के प्रयोग से मई, 1989 से रोक लगा दी है।

(2) अप्रैल, 1997 से बी एच सी के प्रतिपादनों के प्रयोग पर रोक हैं।

(3) कृषि में रासायनिक कृमिनाशियों के प्रयोग की मात्रा को न्यूनतम करने के लिए एकीकृत कृमि प्रबन्ध और पारिस्थितिकी के अनुकूल प्रोद्योगिकी का प्रचार-प्रसार पौध रक्षण के प्रमुख सिद्वांत रहा हैं।

दालों की कीमतें

320. **श्री ईश दत्त यादव** :

चौधरी हरमोहन सिंह यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी हैं कि बाजार में दालें उनके समर्थन मूल्य से तीन गुना अधिक दाम पर बेची जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो व्यापारियों को 200 प्रतिशत का फायदा देने के क्या कारण हैं; और

(ग) किसानों को कम समर्थन मूल्य दिये जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्यय मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) दालों के मूल्य मुख्य रूप में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्यों की तुलना में सामान्यत: अधिक हैं।

(ग) सरकार प्रत्येक मौसम में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों कि दृष्टिकोण तथा ऐसे अन्य प्रांसगिक कारकों के आधार पर जो सरकार के विचार में मूल्यों के निर्धारण के लिये महत्वपूर्ण हैं, दालों (अरहर, मूंग, उड़द तथा चना) सहित प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करती हैं।

मूल्य नीति संबंधी अपनी सिफारिशों का निरूपण करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सभी महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है, जैसे- उत्पादन की लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान/परिणामों मूल्य समानता, मण्डी मूल्यों की प्रवृत्ति, मांग और आपूर्ति की स्थिति, अन्त: फसल मूल्य समानता, औद्योगिकी लागत व्यवस्था पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, रहन-सहन की लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की स्थिति, तथा व्यापार की शर्तें। इस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करने में बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया जाता हैं।

बागवानी के कार्यक्रम

321. **श्रीमती मालती शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र विशेषकर पौड़ी, टिहरी तथा चमोली जनपदों

में बागवानी को बढ़ावा देने तथा किसानों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई कार्यक्रम बना रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इसके लिए प्रत्येक जिले को कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रावधान है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल) : (क) और (ग) कृषि तथा सहकारिता विभाग वर्तमान में पर्वतीय जिलों सहित उत्तर प्रदेश को फलों, सब्जियों, जड़ तथा कन्द फसलें, मशरूम, फूल, मसालें, औषधीय व सुगान्धित पौंधों, ड्रिप सिंचाई तथा संरक्षित कृषि, मधुमक्खी पालन सहित बागवानी विकास तथा कटाई प्रश्चात प्रबंध के लिये अवसंरचना विकास के लिये सहायता प्रदान कर रहा हैं। इनमें से अधिकांश योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्तमान वर्ष के दौरान बागवानी योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 307.27 लाख रू. आबंटित किये गये हैं।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को धनराशि का आबंटन विभिन्न बागवानी योजनाओं के अंतर्गत किया जाता हैं। राज्य सरकारों द्वारा जिलावार आबंटन आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता हैं।

Problems of Pestilence in Andhra Pradesh

322. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether ICAR has studied the problems of pestilence in Andhra Pradesh in 1997-98;

(b) if so, what are the general findings of ICAR in this regard;

(c) whether it is a fact that organic pest control has not been tried by ICAR;

(d) what are the inhibitions of ICAR in promoting organic and natural pest control; and

(e) the steps proposed to reduce dependence on pesticides?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir. A high level committee of scientists was constituted by ICAR to investigate the causes of failure of cotton crop in Andhra Pradesh.

(b) The salient findings of the commit tee are:

1. Cotton crop was severely affected by a combination of unusual weather conditions and heavy pest out-break. The loss was particularly heavy in the northern belt, especially in the three districts of Warangal, Khammam and Karimnagar. The extent of crop loss varied from 25 to 50% with an average of about 30% overall loss in the three affected districts.
2. The cotton crop was severely attacked by pests, particularly Spodoptera litura and Heliothis (Helicoverpa armigera) causing heavy damage not only to cotton but also to sunflower, red-gram, groundnut, gram and chillies.
3. The farmers in the affected areas do not seem to be aware of any IMP methods. Their knowledge is limited in most cases to use of pesticides only.
4. The development of resistance to pesticides in Heliothis is a serious consequence of the misuse of pesticides leading to failure of pest control operations.

(c) No, Sir. Organic Pest control which refers to non-pesticidal methods is an integral part of the Integreated Pest Man agement (IPM) approach. IPM research aims to minimise and even eliminate the use of pesticides. Research has made it possible to manage pests in many crops such as sugarcane without the use of pesticides. Similar efforts are on to de velop non-chemical pest control methods for other crops including cotton.

(d) in view of (c) above, the question does not arise.

(e) (i) Easily adoptable and economically viable IPM packages have been recommended for adoption for major